खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) खाद्य मंत्रालय के अधीन दो उपक्रम अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम हैं । इन उपक्रमों का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

गेहूं का आयात

1439. **श्री रणजीत सिंह :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1992 के "द इक्नामिक टाइम्स" में "व्हीट इम्पोर्ट मूव फेसेज हर्डल्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों से गेहूं का आयात करने के लिए फरवरी, 1992 के मध्य तक कोई समझौता नहीं हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ भेजा गया प्रतिनिधि मंडल वापस आ चुका है; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर कुल कितनी राशि व्यय की गई?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) जी हां ।

(घ) प्रतिनिधि मंडल के दौरे पर लगभग 4.37 लाख रुपए (होटल प्रभारों को छोड़कर) का अनुमानित व्यय हुआ था ।

Requirement of wheat, rice, and oils of states

1440. SHRI PROMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) what are the demands made by different States for the quota of wheat, rice and oil ; and

(b) what is the reaction of Government to these demands State-wise ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) Only some States/UTs send demands for monthly allocations of rice and wheat for the Public Distribution System. A statement showing the States from whom demands were received for the month of March, 1992 is attached. (*See below*).

No demands were invited from the State Governments/UTs for allocation of imported edible oil for the oil year 1991-92 (November—October).

The allocations of rice and wheat from the Central Pool are made on a month basis taking into account the stock in the Central Pool, seasonal availability, offtake trend, relative needs of States/UTs and other related factors.

Allocations of imported edible oils are also made to the States/UTs on a month to month basis depending upon the availability of stocks with STC and after assessing the requirement of each State/UT.